यूरोटेक्स उद्योग और निर्यात लिमिटेड और अन्य

बनाम

महाराष्ट्र राज्य और अन्य

(सिविल अपील संख्या 4491/2016)

08 मई, 2017

[ए. के. सिकरी और अभय मनोहर सप्रे, जे.जे.]

महाराष्ट्र मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2002:

धारा 93 (1), (आई. ए.) और (1 बी.)-महाराष्ट्र मूल्य वर्धित कर (शुल्क, संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, 2009 द्वारा पूर्वव्यापी संचालन-संवैधानिक वैधता-वर्ष 1993 में प्रोत्साहनों की पैकेज योजना-परियोजना योजना के बाहर नई अचल संपत्तियों के अधिग्रहण पर उद्योगों को आनुपातिक प्रोत्साहन देना-योजना से 'आनुपातिक' शब्द हटा दिया गया-'आनुपातिक' शब्द को हटाने के बावजूद, बिक्री कर प्राधिकरणों द्वारा 1993 की योजना के तहत जारी व्यापार परिपत्र में कहा गया है। विस्तार क्षमता के अनुपात में प्रोत्साहन दिया जाएगा-परिपत्र को वैध रूप से जारी नहीं किया गया था क्योंकि प्रशासनिक परिपत्र; 1993 की योजना (जो प्रकृति में वैधानिक थी) के विपरीत, जारी नहीं किया जा सकता था-इसलिए, विधानमंडल ने बॉम्बे बिक्री कर अधिनियम, 1959 (मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2002 के लिए पूर्ववर्ती अधिनियम) में संशोधन किया, जिसमें धारा 41 बीबी शामिल की गई, जो इस संबंध में नियम बनाकर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आनुपातिक प्रोत्साहन प्रदान करती है-हालांकि, कोई नियम नहीं बनाए गए-1959 के अधिनियम को प्रतिस्थापित करके 2002 के अधिनियम को लागू

करना-2002 के अधिनियम की धारा 93 को 2009 के अधिनियम द्वारा पूर्वव्यापी रूप से संशोधित किया गया-जिसे मनमाना, अनुचित, मौलिक अधिकारों के दमनकारी उल्लंघन के रूप में चुनौती दी गई थी। 2002 के अधिनियम के 93 (1) ने स्वयं आनुपातिक प्रोत्साहनों का प्रावधान किया और यह विधायी इरादा उद्देश्यों और कारणों से भी स्पष्ट था-धारा 93 (1) को पूर्वव्यापी प्रभाव देकर अधीनस्थ विधान के रूप में विधायी इरादे को लागू नहीं करने में कार्यपालिका द्वारा की गई पिछली त्रुटि को सुधारना था। वैधानिक नियम और प्रशासनिक कार्रवाई यानी परिपत्र जारी करके इसे प्राप्त करने का प्रयास-इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि नया शुल्क पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ लगाया गया था-इस प्रकार, धारा 93 (1), (IA) और (IB) के पूर्वव्यापी संचालन को बरकरार रखा जाता है।

अपीलों को खारिज करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया

1. बॉम्बे बिक्री कर अधिनियम, 1959 की धारा 41 बी. बी. एक सक्षम प्रावधान नहीं था, लेकिन इसमें प्रतिबंधों के रूप में एक विधायी आदेश था कि प्रोत्साहन की किसी भी पैकेज योजना में कुछ भी निहित होने के बावजूद, पात्रता प्रमाण पत्र रखने वाली एक योग्य इकाई, बिक्री और खरीद के अपने कारोबार के उस हिस्से पर ही लाभ प्राप्त करने की पात्र होगी, जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुपात को लागू करके प्राप्त किया जाएगा। इसलिए, उपरोक्त प्रावधान के पीछे विधायी इरादा स्पष्ट रूप से प्रकट था अर्थात केवल आनुपातिक आधार पर लाभ की अनुमति देना। हालांकि, साथ ही, यह अनुपात निर्धारित करने के लिए सरकार पर छोड़ दिया गया था जिसके आधार पर बिक्री और खरीद के कारोबार का केवल एक हिस्सा प्रोत्साहन के लिए योग्य होगा। [पैरा 22) (409-ई-जी]

2. इसी तरह, जब महाराष्ट्र मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2002 (एम. वी. ए. टी. अधिनियम) लागू किया गया था, तो बिक्री कर अधिनियम की धारा 41बी. बी. में निहित समान प्रावधान को धारा 93 (1) के रूप में शामिल किया गया था। यह इस वैधानिक प्रावधान का कार्यान्वयन है जिसमें सरकार ने गलती की है। हालाँकि, सरकार ने 17 जनवरी, 1998 का परिपत्र जारी करके उस इरादे को पूरा किया, जिसमें अनुपात निर्धारित करके केवल योग्य इकाई की बिक्री या खरीद के कारोबार के उस हिस्से पर लाभ प्रदान किया गया था, लेकिन ऐसा करने का तरीका दोषपूर्ण था। इसे नियमों के माध्यम से निर्धारित करने के बजाय, जो कि उचित प्रक्रिया थी, 1993 की योजना के तहत प्रोत्साहनों के उपयोग पर एक सीमा लागू करने में एक प्रशासनिक परिपत्र के माध्यम से उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास किया गया था। इस कानूनी दुर्बलता के कारण इस परिपत्र को उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था। उच्च न्यायालय के अनुसार, यह वह दोष है जिसे पूर्वव्यापी रूप से उक्त संशोधन करके वैधानिक प्रावधान में संशोधन करके ठीक करने की कोशिश की गई थी। उपरोक्त आधार पर, उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाकर्ताओं के इस तर्क को खारिज कर दिया कि पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ एक नया शुल्क लगाया गया था। [पैरा 22] [409-जी-एच; 410-ए-सी]

3. 1959 के अधिनियम की धारा 41बी. बी. को शामिल करने के समय, 2001 के संशोधन अधिनियम 22 के संशोधन द्वारा, विधेयक को पेश करने के साथ उद्देश्यों और कारणों के विवरण में विशेष रूप से कहा गया था कि संशोधन का उद्देश्य 'राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों में स्थित विस्तार इकाइयों में निर्मित वस्तुओं के अनुपात में प्रोत्साहन अनुदान को प्रतिबंधित करना' था। इस प्रकार, योग्य इकाइयों को आनुपातिक आधार पर प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए उक्त प्रावधान को शामिल करके विधायी इरादे को प्रकट किया गया था। एम. वी. ए. टी. अधिनियम के प्रावधानों से इसी तरह के इरादे को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उक्त अधिनियम की धारा 93 (1) विशेष रूप से 'कुछ

आकस्मिकताओं में एक योग्य इकाई को आनुपातिक प्रोत्साहन' प्रदान करती है। [पैरा 23] [410-डी-ई]

4. यह प्रोत्साहनों की पैकेज योजना (जैसा कि धारा 88,89,90 और 91 के तहत प्रदान किया गया है) की पृष्ठभूमि में है, धारा 93 (1) आनुपातिक प्रोत्साहन प्रदान करती है। एक बार जब यह पाया जाता है कि शुरुआत से ही वैधानिक योजना ने आनुपातिक प्रोत्साहन प्रदान किया था और इस विधायी इरादे को उद्देश्यों और कारणों में भी व्यक्त किया गया था, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि 2009 से पहले इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था और इस तरह का प्रावधान पहली बार वर्ष 2009 में जोड़ा गया था। [पैरा 25] [411-ई-एफ]

5. यह कहना भी सही नहीं है कि 2009 के संशोधन का प्रभाव न्यायालय के निर्णय को बेअसर करने या रद्द करने के लिए था। स्पष्ट इरादा अधीनस्थ विधान यानी वैधानिक नियमों के रूप में विधायी इरादे को लागू नहीं करने में कार्यपालिका द्वारा की गई पिछली त्रुटि को सुधारना और प्रशासनिक कार्रवाई द्वारा इसे प्राप्त करने का प्रयास करना था। [पैरा 26,27] [411-एफ; 412-सी-डी]

6. यदि किसी विधायिका द्वारा पारित किसी कानून को अदालतों द्वारा किसी एक या किसी अन्य कमी के लिए अमान्य होने के रूप में निरस्त कर दिया जाता है, तो यह उपयुक्त विधायिका के लिए उक्त कमी को ठीक करने और एक मान्य कानून पारित करने के लिए सक्षम होगा ताकि उक्त पूर्व कानून के प्रावधानों को पारित होने की तारीख से प्रभावी बनाया जा सके। वर्तमान मामले में, विधायिका ने राज्य सरकार को वह अनुपात/अनुपात निर्धारित करने की शक्ति दी थी जिसमें लाभ दिया जाना था। राज्य सरकार ने उस पर कार्रवाई की, लेकिन गलत तरीके से सत्ता का प्रयोग किया। वैधानिक प्रावधान के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, राज्य विधानमंडल ने स्वयं पूर्वव्यापी रूप से

धारा में संशोधन करके स्थिति को सुधार लिया। [पैरा 29,30] [412-एच; 413-ए-बी, एच; 414-ए-बी]

राय रामकृष्ण बनाम बिहार राज्य ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1667: [1964] एस. सी. आर. 897; एपारी चिन्ना कृष्ण मूर्ति बनाम उड़ीसा राज्य ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 1581: [1964] एस. सी. आर. 185-इसके बाद आया।

हीरालाल रतनलाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1973) 1 एस. सी. सी. 216: 1973 2 एस. सी. आर. 502; बख्तावर ट्रस्ट बनाम एम. डी. नारायण (2003) 5 एस. सी. सी. 298: [2003] 1 पूरक। एस. सी. आर. 1; भारतीय एल्यूमीनियम कंपनी बनाम केरल राज्य (1996) 7 एस. सी. सी. 637: [1996] 2 एस. सी. आर. 23; कृषि आयकर के सहायक आयुक्त और अन्य v. नेटली 'बी' एस्टेट और अन्य (2015) 11 एससीसी 462: [2015] 3 एससीआर 630; आर. सी. टोबैको (पी) लिमिटेड बनाम भारत संघ (2005) 7 एस. सी. सी. 725: [2005] 3 पूरक एस. सी. आर. 342-पर निर्भर।

पश्चिम बंगाल होजरी एसोसिएशन और अन्य v. बिहार राज्य और अन्र (1988) 4 एस. सी. सी. 134: [1988] 2 पूरक एससीआर 378-विभेदत्म्क।

ब्रिटिश फिजिकल लैब इंडिया लिमिटेड बनाम कर्नाटक राज्य और अन्यः (1999) 1 एस. सी. सी. 170-संदर्भित।

7. जिस व्यापारी पर कर लगाया जाता है, वह उपभोक्ताओं पर कर लगाने की स्थिति में नहीं है, उसकी विधायिका की क्षमता के लिए कोई प्रासंगिकता नहीं है। [पैरा 36] [418-एफ]

जे. के. जूट मिल्स कं. लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 1534: [1962] एस. सी. आर. 1-इसके बाद आया।

आर. सी तंबाकू (पी). लिमिटेड बनाम भारत संघ (2005) 7 एस. सी. सी. 725: [2005) 3 पूरक एस. सी. आर. 342-पर निर्भर।

मामला कानून संदर्भ

(1988) 2 पूरक एस. सी. आर. 378 विशिष्ट पैरा 14

(1999) 1 एस सी सी 170 पैरा 14

(1973) 2 एस. सी. आर. 502 पैरा 18

[1964] एस. सी. आर. 897 पैरा 29

[1964] एस. सी. आर. 185 पैरा 30

[2003) 1 सप्लीमेंट एस. सी. आर. 1 पैरा 32

[1996) 2 एस. सी. आर. 23 पैरा 33

[2015] 3 एस. सी. आर. 630 पेरा 34

[2005] 3 सप्लीमेंट एस. सी. आर. 342 पेरा

[1962] एस. सी. आर. 1 पैरा 35 पर निर्भर था।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या- 4491/2016

2009 की सिविल रिट याचिका संख्या 8431 में मुंबई में बॉम्बे उच्च न्यायालय के 10.06.2013 के निर्णय और आदेश से

के साथ

2016 के सी. ए. संख्या 4492,4495,4497 और 4499

सी. यू. सिंह, ए. के. गांगुली, एस. गणेश, बीरबल सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, अर्जुन हरकौली, निखिल नय्यर, दिलीप सी डागा, एन. साई विनोद, सुश्री स्मृति शाह, दिव्यांशु राय, प्रशांत पी., रूपिंदर सिंहमान, अभिषेक बघेल, राजेश कुमार, आर. के. श्रीवास्तव, राहुल चिटनिस, सुश्री रमनी तनेजा, अनिल श्रीवास्तव, अधिवक्ता अपीलार्थियों के लिए।

अनिरुद्ध पी. मयी, निशांत रमाकांतराव कटनेश्वरकर, अर्पित राय, अधिवक्ता प्रतिवादी के लिए

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

ए. के. सिकरी, जे.

1. ये अपीलें बॉम्बे उच्च न्यायालय के 10 जून, 2013 के फैसले से उत्पन्न होती हैं, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाओं के एक समूह को खारिज कर दिया है, जिसमें महाराष्ट्र मूल्य वर्धित कर (शुल्क, संशोधन और वैधता) अधिनियम, 2009 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी, जिसने 1 अप्रैल, 2005 से पूर्वव्यापी प्रभाव से महाराष्ट्र मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2002 (संक्षेप में, 'एमवीएटी अधिनियम') के कुछ प्रावधानों में संशोधन किया था। उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करते हुए अपने निर्णय को आधारित किया है जिसमें कहा गया है कि विधानमंडल के पास संभावित और साथ ही पूर्वव्यापी रूप से अधिनियमित करने की शक्ति है। अपीलार्थियों को इस प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है और वास्तव में संभवतः नहीं हो सकती है। हालाँकि, उनका तर्क है कि उच्च न्यायालय औद्योगिक इकाइयों पर प्रभावों और परिणामों और पूर्वव्यापी संशोधन के व्यावहारिक

प्रभाव की सराहना करने में विफल रहा है, जिन्होंने राज्य सरकार की योजना के जवाब में महाराष्ट्र के सबसे बेहद पिछड़े क्षेत्रों में भारी निवेश किया था और जिनके कारण यह माना गया था कि वे अपने उत्पादन के 100% पर मूल्य वर्धित कर (संक्षेप में, 'VAT') से छूट का दावा करने के हकदार थे और तदनुसार अपने ग्राहकों से कोई VAT वसूल नहीं किया। उनके अनुसार, इस संशोधन का प्रभाव और परिणाम यह था कि 1 अप्रैल, 2005 से पूर्वव्यापी प्रभाव से, जिन औद्योगिक इकाइयों ने महाराष्ट्र राज्य के बहुत पिछड़े क्षेत्रों में पूंजी निवेश किया था और जो पहले अपनी संबंधित औद्योगिक इकाइयों के पूरे उत्पादन पर वैट छूट लाभ का दावा करने के हकदार थे, उनके छूट लाभ में काफी कटौती की गई थी, जो उपरोक्त पूर्वव्यापी संशोधन के कारण इकाई के कुल उत्पादन के केवल एक हिस्से तक सीमित था।

2. इस पृष्ठभूमि में मुद्दा यह है कि क्या एम. वी. ए. टी. अधिनियम में पूर्वव्यापी संशोधन संवैधानिकता की कसौटी पर खरा उतरता है और कानून में वैध है। विवाद की सटीक प्रकृति और एक ओर अपीलार्थी और दूसरी ओर प्रत्यर्थी द्वारा लिए गए निर्णयों को समझने के लिए निम्नलिखित तथ्यात्मक पृष्ठभूमि पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

3. पिछड़े और अविकसित क्षेत्रों में औद्योगीकरण को प्रोत्साहित करने और सुनिश्चित करने के लिए, महाराष्ट्र सरकार ने ऐसे क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन देने के लिए पैकेज योजनाएं शुरू की थीं। इस प्रक्रिया में पहली योजना को 'प्रोत्साहन पैकेज योजना' के रूप में जाना जाता है जिसे वर्ष 1964 में शुरू किया गया था। फिर बाद के वर्षों में कुछ संशोधित योजनाएं आईं। 30 सितंबर, 1988 को 1 अक्टूबर, 1988 से 30 सितंबर, 1993 के बीच की अवधि के लिए प्रोत्साहनों की एक और नई पैकेज योजना को प्रोत्साहन जारी करने के दायरे, पैमाने

और तरीके को तर्कसंगत बनाने और राज्य के विकसित क्षेत्रों से अविकसित क्षेत्रों में उद्योगों के फैलाव में तेजी लाने के उद्देश्य से जारी किया गया था। इसे 07 मई, 1993 से अधिसूचित किया गया था, जिससे यह मामला संबंधित है।

4. इस योजना का उद्देश्य बॉम्बे ठाणे-पुणे क्षेत्र के बाहर उद्योगों को फैलाना और उन्हें राज्य के अविकसित और विकासशील क्षेत्रों, विशेष रूप से बॉम्बे ठाणे-पुणे क्षेत्र से दूर के क्षेत्रों की ओर आकर्षित करना था। योजना के पैराग्राफ 3.8 (I) (i) (c) में निम्नलिखित प्रावधान हैं -

"3.8 सकल स्थिर पूँजी निवेश-

(I) सकल स्थिर पूँजी निवेश का अर्थ होगा और इसमें शामिल होगा-

(i) नई स्थिर परिसंपत्तियाँ-स्थल पर अर्जित और इसके लिए भुगतान की गई नई स्थिर परिसंपत्तियों का मूल्यः

स्पष्टीकरण

(ए)

(बी)

(सी) कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा स्वीकृत परियोजना योजना के बाहर नई स्थिर संपत्ति के किसी भी अधिग्रहण पर अवशिष्ट योग्य अवधि के दौरान आनुपातिक प्रोत्साहन के उद्देश्यों के लिए विचार किया जा सकता है, बशर्ते कि ऐसा अधिग्रहण पात्र इकाई के पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में सकल स्थिर पूंजी निवेश के 25 प्रतिशत से कम न हो।"

5. 6 जुलाई, 1994 के सरकारी प्रस्ताव (जी. आर.) द्वारा, अनुच्छेद 3.8 (I) (i) (सी) में संशोधन किया गया और 1993 की योजना से 'आनुपातिक' शब्द को हटा दिया गया। नतीजतन, यह निर्धारित किया गया था कि कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा स्वीकृत परियोजना योजना के बाहर नई अचल संपत्तियों के अधिग्रहण पर विशेष पूंजी प्रोत्साहन के अलावा अन्य प्रोत्साहनों के लिए विचार किया जा सकता है यदि अधिग्रहण सकल निश्चित पूंजी निवेश के 25 प्रतिशत से कम नहीं था। हालांकि, बिक्री कर लाभ के उद्देश्यों के लिए, पात्रता की मात्रा एक नई इकाई के लिए स्वीकार्य 75 प्रतिशत तक सीमित होगी। मौजूदा इकाइयाँ भी खंड के लाभों की हकदार थीं।

6. 1993 की योजना में 'आनुपातिक' शब्द को हटाने के बावजूद, 17 जनवरी, 1998 को बिक्री कर आयुक्त द्वारा व्यापार परिपत्र जारी किया गया था, जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि 1993 की योजना के तहत प्रोत्साहन कुल क्षमता के विस्तार क्षमता या नए निश्चित पूंजी निवेश के निवेश अनुपात के अनुपात में विस्तार/निवेश के बाद कुल सकल निश्चित पूंजी निवेश के अनुपात में दिया जाएगा, न कि ऐसी श्रेणी के तहत शामिल एक योग्य इकाई के पूरे उत्पादन पर। इस परिपत्र के अधिकारों को उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करके चुनौती दी गई थी। जबकि ये रिट याचिकाएं लंबित थीं, महाराष्ट्र बिक्री कर न्यायाधिकरण ने 17 मार्च, 2001 के अपने फैसले में कहा कि उपरोक्त परिपत्र वैध रूप से जारी नहीं किया गया था क्योंकि ऐसा प्रशासनिक परिपत्र जारी नहीं किया जा सकता था, जो 1993 की योजना के विपरीत था, जैसा कि संशोधित किया गया था, क्योंकि ऐसी योजना वैधानिक प्रकृति की थी। यह उल्लेख किया जा सकता है कि ट्रिब्यूनल के उपरोक्त आदेश को बाद में उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था और इसे अंतिम रूप दिया गया था। इस कठिनाई को दूर करने के लिए, विधानमंडल ने धारा 41 बीबी को शामिल करने के साथ बॉम्बे बिक्री कर अधिनियम, 1959 में संशोधन किया। यह प्रावधान इस प्रकार हैः

"41 बी.बी.-कुछ आकस्मिकताओं में एक योग्य इकाई को आनुपातिक प्रोत्साहन।

(1) प्रोत्साहनों की किसी भी पैकेज योजना में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, कोई भी पात्र इकाई, जिसे पात्रता प्रमाण पत्र दिया गया है, वर्तमान वर्ष में या किसी भी वर्ष में, चाहे वह 2001 के महाराष्ट्र अधिनियम 22 की धारा 12 के प्रारंभ होने की तारीख से पहले या बाद में हो, केवल बिक्री या खरीद के अपने कारोबार के उस हिस्से पर लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होगी, जो उस वर्ष में उक्त इकाई की बिक्री और खरीद के कुल कारोबार के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुपात को लागू करके प्राप्त किया जा सकता है और विभिन्न वर्गों के विक्रेताओं और विभिन्न योजनाओं के लिए अलग-अलग अनुपात निर्धारित किए जा सकते हैं।

(2) उप-धारा (1), यदि कोई हो, के उल्लंघन में किसी पात्र इकाई द्वारा प्राप्त लाभ वापस लिए गए माने जाएंगे और ऐसी इकाई, उप-धारा (1) के तहत किए गए कारोबार से अधिक बिक्री और खरीद के कारोबार के संबंध में कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी और तदनुसार कोई भी लाभ जो वापस लिया जाता है, उप-धारा (3) में दिए गए कर के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा।

(3) उप-धारा (2) में उपबंधित कर के बकाया की वसूली के लिए, आयुक्त इकाई से, लिखित आदेश द्वारा, ऐसे कारोबार पर कर, ब्याज और जुर्माने का भुगतान करने की अपेक्षा करेगा, जिस पर लाभ उपलब्ध नहीं हैं और विक्रेता की मांग की सूचना पर उसी के अनुसार

कार्य करेगाः बशर्ते कि, इस धारा के तहत कोई भी आदेश विक्रेता को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा। स्पष्टीकरण-धारा 41 बी. ए. और 41 बी. बी. में निहित प्रावधानों के प्रयोजनों के लिए "मौजूदा इकाई, योग्य इकाई, कार्यान्वयन एजेंसी, पात्रता प्रमाण पत्र और पात्रता प्रमाण पत्र" शब्दों का वही अर्थ होगा जो प्रोत्साहन की संबंधित पैकेज योजना में दिया गया है। हालाँकि, यह उल्लेख करना उचित होगा कि यद्यपि धारा 41 बी. बी. ने आनुपातिक प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया है, लेकिन यह राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में नियम बनाकर निर्धारित किया जा सकता है। हालांकि, कभी भी कोई नियम नहीं बनाए गए।"

7. इस प्रावधान ने स्पष्ट रूप से आनुपातिकता की अवधारणा को प्रस्तुत किया, जो उस विधेयक के परिचय के साथ उद्देश्यों और कारणों के विवरण से भी स्पष्ट है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अधिनियम में संशोधन 'राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में स्थित विस्तार इकाइयों में निर्मित वस्तुओं के अनुपात में प्रोत्साहन अनुदान को प्रतिबंधित करने के लिए' किया जा रहा था।

8. वर्ष 2002 में, वैट व्यवस्था शुरू की गई और महाराष्ट्र राज्य ने एम. वी. ए. टी. अधिनियम भी लागू किया जिससे बॉम्बे बिक्री कर अधिनियम, 1959 की जगह ली गई। यह 1 अप्रैल, 2005 को लागू हुआ। एम. वी. ए. टी. अधिनियम की धारा 8 (4) राज्य सरकार को धारा 88 में परिभाषित पात्रता प्रमाण पत्र रखने वाली इकाई द्वारा माल की बिक्री के किसी भी वर्ग या वर्गों के संबंध में पूरे कर के भुगतान से छूट प्रदान करने का अधिकार देती है, जिसे कर के भुगतान से छूट के रूप में प्रोत्साहन की किसी भी पैकेज योजना के तहत प्रोत्साहन दिया जाता है। एम. वी. ए. टी. अधिनियम की

धारा 93 कुछ आकस्मिकताओं में एक योग्य इकाई को आनुपातिक प्रोत्साहन से संबंधित है। इसकी उप-धारा

(1), जैसा कि यह मूल रूप से थी, निम्नानुसार हैः

"93. कुछ आकस्मिकताओं में किसी पात्र इकाई को आनुपातिक प्रोत्साहन-

(I) प्रोत्साहन की किसी भी पैकेज योजना में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, कोई भी पात्र इकाई जिसे पात्रता प्रमाण पत्र दिया गया है, किसी भी वर्ष में, नियत दिन के बाद, केवल बिक्री या खरीद के अपने कारोबार के उस हिस्से पर लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होगी, जो उस वर्ष में उक्त इकाई की बिक्री और खरीद के कुल कारोबार के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुपात को लागू करके प्राप्त किया जा सकता है और विभिन्न वर्गों की इकाइयों और विभिन्न योजनाओं के लिए अलग-अलग अनुपात निर्धारित किए जा सकते हैं।

xx xx xx

9. यह वह प्रावधान है जिसे 2009 के संशोधन अधिनियम द्वारा पूर्वव्यापी रूप से संशोधित किया गया है और यह विवाद का मूल है। संशोधित प्रावधान अब इस प्रकार हैः

"(1क) प्रोत्साहन की किसी भी पैकेज योजना में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, कोई भी पात्र इकाई, जिसे उत्पादन क्षमता में वृद्धि या, यथास्थिति, नई निश्चित पूंजी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के कारण निर्धारित दिन से पहले या बाद में किसी भी समय पात्रता प्रमाण पत्र और पात्रता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है, किसी

भी वर्ष में लाभ प्राप्त करने का हकदार होगा, केवल बिक्री या खरीद के अपने कारोबार के उस हिस्से पर जो उस वर्ष में उक्त इकाई की बिक्री और खरीद के कुल कारोबार के लिए उप-धारा (आई. ए.) के प्रावधानों को लागू करके प्राप्त किया जा सकता हैः

(1क) यदि पात्र इकाई ने, (क) बिक्री के अलग खाते बनाए रखे हैं और

(1क) जहां पात्र इकाई ने (क) बिक्री और खरीद के अलग-अलग खाते बनाए रखे हैं और उत्पादन क्षमता में वृद्धि से संबंधित बिक्री और खरीद की पहचान करने में सक्षम है या, जैसा भी मामला हो, उक्त योग्य निवेश, तो लाभों के लिए पात्र कारोबार का हिस्सा केवल ऐसी पहचान के आधार पर तय किया जाएगा;

(ख) बिक्री और खरीदार के अलग-अलग खाते नहीं रखे गए हैं और उत्पादन क्षमता में वृद्धि के संबंध में बिक्री और खरीद की पहचान करने में सक्षम नहीं है या, जैसा भी मामला हो, उक्त योग्य निवेश, तो ऐसे लाभों की गणना उपखंड (i) में सूत्रों को लागू करने के बाद की जाएगी या, जैसा भी मामला हो, उपखंड (ii) के तहत दी गई हैः

(i) यदि उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है, तो 1988 के लिए प्रोत्साहन पैकेज योजना या, जैसा भी मामला हो, 1993 के लिए प्रोत्साहन पैकेज योजना के लिए सूत्र निम्नानुसार होंगेः

$$\text{योग्य टर्नओवर} = \frac{\text{टर्नओवर x योग्य टर्नओवर में वृद्धि}}{\text{उत्पादन क्षमता ऐसी वृद्धि के बाद कुल उत्पादन क्षमता}}$$

(ii) जहां उत्पादन क्षमता में कोई वृद्धि नहीं होती है, तो 1993 के लिए प्रोत्साहन पैकेज योजना के लिए सूत्र निम्नानुसार होंगेः

योग्य टर्नओवर = <u>टर्नओवर x नया निश्चित योग्य टर्नओवर</u>

पूंजी निवेश कुल सकल निश्चित पूंजी निवेश

(I B) जब योग्य टर्नओवर में कई तैयार उत्पाद शामिल होते हैं, तो-

(a) प्रत्येक तैयार उत्पाद की उत्पादन क्षमता को संबंधित योग्य निर्धारित करने में अलग से विचार किया जाएगा। और

(ख) योग्य कारोबार उन उत्पादों से संबंधित होगा जिन पर योग्य निवेश का प्रभाव पड़ा है और जब योग्य निवेश उत्पादन क्षमता में वृद्धि नहीं करता है, तो यह सभी तैयार उत्पादों पर लागू होगा।

इसके साथ ही, धारा 93 ए को यह प्रावधान करने के लिए जोड़ा गया है कि धारा 93 उन सभी योग्य इकाइयों पर लागू होगी, जिन्हें किसी भी प्रोत्साहन पैकेज योजना के तहत पात्रता प्रमाण पत्र और पात्रता प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं; यदि ऐसे प्रमाण पत्र नियत दिन (1 अप्रैल 2005) को या उससे पहले जारी किए गए हैं, तो निर्धारित दिन से और किसी अन्य मामले में, ऐसे प्रमाण पत्रों में उल्लिखित प्रभाव की तारीख से।

10. 2009 के संशोधन अधिनियम 22 की धारा 5 में एक सत्यापन और बचत प्रावधान है जो इस प्रकार हैः

> "5 (1) इसके विपरीत, किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में कुछ भी निहित होने के बावजूद, महाराष्ट्र मूल्य वर्धित कर (लेवी, संशोधन और सत्यापन) अधिनियम, 2009 (इसके बाद "उक्त अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के प्रारंभ

की तारीख से पहले, किसी भी विक्रेता या व्यक्ति द्वारा की गई बिक्री या खरीद के संबंध में कोई सहायक समीक्षा, लेवी या कर का संग्रह, या महाराष्ट्र मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2002 (इसके बाद इस धारा में "मूल्य वर्धित कर अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों के तहत ऐसे मूल्यांकन, समीक्षा, लेवी या संग्रह के संबंध में की गई कोई कार्रवाई या कार्य, वैध और प्रभावी माना जाएगा जैसे कि ऐसा मूल्यांकन, समीक्षा, लेवी या संग्रह या कार्रवाई।

(क) राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा ऐसे किसी कर के निर्धारण, समीक्षा, उद्ग्रहण या संग्रह के संबंध में किए गए या किए गए सभी कार्य, कार्यवाहियां या कार्य, सभी उद्देश्यों के लिए, यह माना जाएगा और हमेशा कानून के अनुसार किया गया या लिया गया है;

(ख) इस प्रकार भुगतान किए गए किसी कर की वापसी के लिए कोई मुकदमा, अपील, आवेदन या अन्य कार्यवाहियां किसी भी न्यायालय में या किसी भी न्यायाधिकरण, अधिकारी या अन्य प्राधिकरण के समक्ष नहीं रखी जाएंगी या जारी नहीं रखी जाएंगी, और

(ग) कोई भी न्यायालय, न्यायाधिकरण, अधिकारी या अन्य प्राधिकरण ऐसे किसी कर की वापसी का निर्देश देने वाले किसी आदेश या आदेश को लागू नहीं करेगा।

(2) शंकाओं को दूर करने के लिए, एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उप-धारा (1) की किसी भी बात का अर्थ किसी व्यक्ति को,

(क) उक्त अधिनियम द्वारा संशोधित मूल्य वर्धित कर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पूछताछ करने से, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट कर का कोई निर्धारण, समीक्षा, उद्ग्रहण या संग्रह करने से, या

(ख) उक्त अधिनियम द्वारा संशोधित मूल्य वर्धित कर अधिनियम के तहत कर के रूप में उससे देय राशि से अधिक भुगतान किए गए किसी कर की वापसी का दावा करने से नहीं लगाया जाएगा।

(3) उक्त अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल्य वर्धित कर अधिनियम की कोई बात किसी व्यक्ति को उक्त अधिनियम के प्रारंभ से पहले उसके द्वारा किए गए किसी भी कार्य या किए जाने में चूक के संबंध में किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं बनाएगी, यदि ऐसा कार्य या चूक मूल्य वर्धित कर अधिनियम के तहत अपराध नहीं था, बल्कि उक्त अधिनियम द्वारा किए गए संशोधनों के लिए था; और न ही ऐसे कार्य या चूक के संबंध में कोई व्यक्ति उस दंड के अधीन होगा जो उक्त अधिनियम के प्रारंभ से तुरंत पहले लागू कानून के तहत उस पर लगाया जा सकता था।"

11. जैसा कि शुरुआत में ही बताया गया है, यह केवल एम. वी. ए. टी. अधिनियम की धारा 93 की उप-धाराओं (1), (आई. ए.) और (आई. बी.) का पूर्वव्यापी संचालन है जो चुनौती का विषय है।

12. उच्च न्यायालय ने उक्त संशोधन के पूर्वव्यापी संचालन को इस आधार पर अनुमेय ठहराने वाली चुनौती को खारिज कर दिया है कि यह एक वैध विधान की प्रकृति में था और इस तरह के कानून को विधानमंडल द्वारा पूर्वव्यापी प्रभाव से पारित

किया जा सकता है, खासकर तब जब विधानमंडल को पूर्वव्यापी रूप से कानूनों को लागू करने का अधिकार हो।

13. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस. गणेश ने प्रस्तुत किया कि ऊपर बताई गई घटनाओं का कालक्रम स्पष्ट रूप से यह स्थापित करता है कि राज्य सरकार और कर अधिकारियों ने 2005 से 2009 की प्रासंगिक अवधि के दौरान सभी औद्योगिक इकाइयों को एक प्रामाणिक विश्वास दिलाया कि वैट छूट का लाभ औद्योगिक इकाई के पूरे उत्पादन के संबंध में उपलब्ध होगा, न कि केवल उसके एक आनुपातिक हिस्से के संबंध में। इसलिए, इन औद्योगिक इकाइयों को अक्षम कर दिया गया था और उनके उत्पादन के किसी भी हिस्से पर किसी भी वैट की वसूली से रोक दिया गया था, क्योंकि यह अवैध होता और वास्तव में एक आपराधिक अपराध होता। यदि यही संशोधन वर्ष 2005 में ही किया गया होता, तो औद्योगिक इकाइयों को लंबे समय तक वैट छूट का लाभ मिलता और 2005 से अपने कुल उत्पादन के उचित अनुपात पर अपने ग्राहकों से वैट वसूल किया जाता। उन्होंने तर्क दिया कि पूर्वव्यापी संशोधन के लिए उत्तरदाताओं द्वारा दिया गया एकमात्र कारण या औचित्य यह है कि राज्य सरकार को काफी मात्रा में राजस्व का नुकसान हो रहा है। ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि राज्य सरकार की प्रोत्साहन योजना के जवाब में महाराष्ट्र के अत्यंत पिछड़े क्षेत्रों में भारी मात्रा में पूंजी निवेश किया गया था। इस प्रकार, राज्य सरकार ने प्रोत्साहन योजना के तहत अपने सभी उद्देश्यों और लक्ष्यों को पूरी तरह से प्राप्त किया। इसके बाद योजना के लाभों में उल्लेखनीय कमी करना पूरी तरह से अनुचित, मनमाना और अनुचित है। इसके अलावा, पूर्वव्यापी संशोधन के दोहरे प्रभाव यह हैं कि, पहला, औद्योगिक इकाइयों को उनके द्वारा किए गए पूंजी निवेश के कारण छूट लाभ के एक हिस्से से स्थायी रूप से वंचित कर दिया जाता है, हालांकि छूट की अवधि समाप्त होने से पहले वर्षों का समय लगता है। दूसरा, औद्योगिक इकाइयों को अपने ग्राहकों से वैट की राशि की वसूली करने

के किसी भी अवसर से स्थायी रूप से वंचित कर दिया जाता है क्योंकि वे अक्षम थे और प्रभावी रूप से संबंधित अवधि में इसे वसूल करने से रोक दिया गया था। इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि पूर्वव्यापी संशोधन मनमाना, अनुचित और दमनकारी है और इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 (1) (जी) के तहत अपीलार्थी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

14. उन्होंने तर्क दिया कि जहां सरकार ने ऐसी स्थिति पैदा की है जो एक निर्माता/डीलर के लिए अपने ग्राहकों से बिक्री कर/वैट की वसूली को अवैध या असंभव बनाती है, तो कर की राशि की कोई मांग नहीं की जा सकती है, जैसा कि पश्चिम बंगाल होजरी एसोसिएशन और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य, (1988) 4 एससीसी 134 और ब्रिटिश फिजिकल लैब इंडिया लिमिटेड बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य, (1999) 1 एससीसी 170 में कहा गया है। इस ओर से, उन्होंने बताया कि 2005 से 2009 की अवधि के दौरान, अपीलकर्ता और उक्त छूट के दायरे में आने वाले अन्य उद्योग, अपने-अपने विस्तारित उपक्रमों के पूरे कारोबार पर बिक्री कर छूट लाभ का दावा करने के हकदार थे, केवल इसलिए कि राज्य सरकार द्वारा कोई नियम नहीं बनाया गया था, पहले बिक्री कर अधिनियम की धारा 41बीबी के तहत और उसके बाद वैट अधिनियम की धारा 85 के तहत। नतीजतन, अपीलार्थी और अन्य उद्योगों को प्रभावी रूप से अक्षम कर दिया गया और उनके कारोबार के किसी भी हिस्से पर बिक्री कर या वैट की वसूली करने से प्रतिबंधित कर दिया गया। वास्तव में, यदि अपीलार्थी अपने ग्राहकों से अपने कारोबार के किसी भी हिस्से पर बिक्री कर वसूल करता है, तो अपीलार्थी वैट अधिनियम के तहत आपराधिक अपराध का दोषी होता। यह प्रतिवादी हैं जो इस स्थिति के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, जिसे केवल धारा 41 बीबी या धारा 93 के तहत एक नियम तैयार करके तुरंत समाप्त किया जा सकता था। तदनुसार, अपीलार्थी ने अपने विस्तारित उपक्रम के कारोबार के 100% पर कर छूट का लाभ

उठाया और अपीलार्थी के ग्राहकों को छूट का लाभ दिया। इस प्रक्रिया में, अपीलार्थी ने अपने कुल निश्चित पूंजी निवेश के 130% पर गणना किए गए अपने पूरे कर छूट लाभ को समाप्त कर दिया, अपीलार्थी की 15 साल की छूट अवधि की समाप्ति से बहुत पहले जो केवल 2015 में समाप्त हुई थी। अपनी बिक्री कर छूट लाभ सीमा समाप्त होने के तुरंत बाद, अपीलार्थी ने अपने ग्राहकों से वैट की वसूली शुरू कर दी और कर अधिकारियों को उसी का भुगतान करना शुरू कर दिया।

15. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि 1 अप्रैल, 2005 से 2009 में किए गए विवादित पूर्वव्यापी संशोधन के सटीक प्रभाव और प्रभाव को स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है, जैसा कि नीचे दिया गया हैः

(क) कुल छूट लाभ जिसके लिए एक निर्माता हकदार था, किसी भी स्थिति में, विस्तार में कुल योग्य निश्चित पूंजी निवेश के 130% तक सीमित था, जिसका लाभ 15 वर्षों की लंबी अवधि में उठाया जा सकता था। पूर्वव्यापी संशोधन का प्रभाव यह है कि एक उपक्रम जो पहले से ही अपने कारोबार के 100% पर छूट लाभ का लाभ उठा चुका है, पूर्वव्यापी संशोधन के परिणामस्वरूप, उसके द्वारा की गई किसी भी गलती के बिना, अपनी छूट लाभ पात्रता का एक टुकड़ा पूरी तरह से जब्त कर लेगा।

(बी) यदि उक्त संशोधन 1 अप्रैल, 2005 को ही किया गया था (धारा 93 के तहत नियम जारी करने की सरल विधि द्वारा), तो अपीलकर्ता ने केवल अपने कारोबार के आनुपातिक हिस्से पर कर छूट का लाभ उठाया होगा और अपने कारोबार के शेष (कर योग्य) हिस्से पर वैट की वसूली की होगी। आक्षेपित पूर्वव्यापी संशोधन के परिणामस्वरूप, अपीलार्थी को न केवल अपनी छूट पात्रता (अपने पूंजी निवेश के आधार पर) के एक हिस्से से स्थायी रूप से वंचित कर दिया जाता है, बल्कि अपने ग्राहकों से

अपने कारोबार के उस अनुपात पर वैट वसूल करने के अवसर से भी स्थायी रूप से वंचित कर दिया जाता है जो कर योग्य है।

(ग) विचाराधीन सभी उद्योगों पर उक्त दोहरे प्रतिकूल प्रभाव के लिए कोई वारंट या औचित्य नहीं है। अपीलार्थी सहित उन सभी ने प्रचलित कानून के तहत उनसे जो कुछ भी अपेक्षित था, उसे विधिवत रूप से पूरा किया है। उन्होंने महाराष्ट्र राज्य के सबसे पिछड़े जिलों में भारी पूंजी निवेश किया और अपने उपक्रमों के उत्पादन और कारोबार में महत्वपूर्ण वृद्धि की और इस तरह महाराष्ट्र राज्य के कर आधार का बहुत विस्तार किया।

(घ) महाराष्ट्र राज्य के वकील ने पूर्वव्यापी संशोधन के लिए यह कहने के अलावा कोई स्पष्टीकरण या औचित्य नहीं दिया कि यह एक त्रुटि या विसंगति को सुधारने के लिए था, जो कि, जैसा कि पहले ही बताया गया है, एक असमर्थनीय तर्क था।

16. श्री अनिल श्रीवास्तव, विद्वान वकील, जो 2016 की सिविल अपील संख्या 4499 में उपस्थित हुए, ने अतिरिक्त रूप से तर्क दिया कि संशोधन अधिनियम 2009 के माध्यम से पूर्वव्यापी संशोधन एक अस्पष्टता को दूर करने या अयोग्यता के कारण को ठीक करने का प्रयास नहीं करता है, बल्कि संक्षेप में, पहली बार अपीलार्थी पर कर का एक नया शुल्क लगाने का प्रयास करता है, जो अनुचित और मनमाना है और इसलिए, भारत के संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर होने के कारण इसे निरस्त किया जा सकता है। इस ओर से उनका निवेदन था कि उच्च न्यायालय इस बात पर विचार करने में विफल रहा कि पूर्वव्यापी प्रभाव से किए गए संशोधन का एकमात्र उद्देश्य 27 जुलाई, 2009 के फैसले और बॉम्बे उच्च न्यायालय के 13 अक्टूबर, 2008 और 19 जून, 2009 के आदेशों के प्रभाव को बेअसर करना था, जो अनुमेय नहीं था। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि विधानमंडल न्यायालय के निर्णय को बेअसर करने या अति-

निर्णय देने के एकमात्र उद्देश्य के साथ कानून नहीं बना सकता है। श्री श्रीवास्तव का एक अन्य निवेदन था कि अपीलार्थी के पक्ष में निहित अधिकार बनाए गए थे और वर्तमान मामले में प्रोमिसरी एस्टोपल का सिद्धांत भी लागू था और इन पहलुओं ने विधानमंडल को पूर्वव्यापी रूप से संशोधन करने से रोक दिया था। उन्होंने उपरोक्त प्रस्तावों पर कई निर्णयों का उल्लेख किया।

17. शेष अपीलों में उपस्थित अन्य वकीलों ने उपरोक्त तर्कों को अपनाया।

18. राज्य के विद्वान वकील ने अपीलार्थियों के वकील की उपरोक्त दलीलों का खंडन किया और दलील दी कि उच्च न्यायालय के सुविचारित निर्णय में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि शुरू से ही, विधायी इरादा केवल आनुपातिक आधार पर प्रोत्साहन पैकेज योजना के तहत लाभ की अनुमति देना था जो बिक्री कर अधिनियम की धारा 41बीबी के साथ-साथ एमवीएटी अधिनियम की धारा 93 में परिलक्षित होता है। इन धाराओं के तहत, राज्य सरकार को ऐसे लाभों के लिए पात्र इकाई की बिक्री और खरीद के कारोबार के हिस्से की गणना के लिए अनुपात निर्धारित करके प्रोत्साहन के पैकेज योजना के तहत लाभों के अनुदान को आनुपातिक रूप से सीमित करने के लिए तौर-तरीके तैयार करने की आवश्यकता थी। उन्होंने कहा कि हालांकि राज्य सरकार द्वारा इस अनुपात को निर्धारित करने वाले कोई नियम नहीं बनाए गए थे, इसके बजाय बिक्री कर आयुक्त ने इस संबंध में 17 जनवरी, 1998 को प्रशासनिक परिपत्र जारी किया, जिसे अदालतों द्वारा इस आधार पर अस्वीकार्य करार दिया गया था कि '1993 की योजना के तहत किसी भी प्रावधान के अभाव में और वैकल्पिक रूप से, नियम बनाकर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किसी भी अनुपात के अभाव में, बिक्री कर उपायुक्त को निर्धारिती को 1993 की योजना के तहत नई अधिग्रहित अचल संपत्तियों के कारण होने वाले उत्पादन के अनुपात में प्रोत्साहन का

लाभ उठाने का निर्देश देने का अधिकार नहीं था।' उपरोक्त उद्धृत भाग का उल्लेख करते हुए, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने लाभों को प्रतिबंधित करने के विधायी इरादे के अस्तित्व को मान्यता दी, लेकिन निष्कर्ष निकाला कि कोई नियम नहीं बनाकर उस इरादे को प्रभावी बनाने में एक कमी/विसंगति थी। यही कारण है कि उपर्युक्त कमी को दूर करने के लिए वर्ष 2009 में पूर्वव्यापी प्रभाव से वैट अधिनियम में संशोधन किया गया था। विद्वान वकील के अनुसार, इस तरह का कदम राज्य विधानमंडल की क्षमता के भीतर था और कानून में इसकी बहुत अनुमति थी। उन्होंने विभिन्न निर्णयों का भी उल्लेख किया जो यह दर्शाते हैं कि न केवल विधानमंडल को एक कानून बनाने का अधिकार है, जिसमें एक राजकोषीय क़ानून भी शामिल है, या तो संभावित रूप से या पूर्वव्यापी रूप से, बल्कि विधानमंडल को उस आधार को हटाकर कानून को पूर्वव्यापी रूप से बदलकर न्यायिक निर्णय के प्रभाव को रद्द करने का भी अधिकार है, जिसके आधार पर निर्णय लिया गया था। विद्वान अधिवक्ता ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी वर्ष में प्रोत्साहन पैकेज योजना के तहत दिए जाने वाले लाभों को अतिरिक्त पूंजी निवेश के अनुपात तक सीमित रखना लोक हित में है क्योंकि यह विभिन्न क्षेत्रों के बीच कर के बोझ को संतुलित करता है और राज्य के वित्तीय संसाधनों की एक अस्थिर निकासी को रोकता है। विधानमंडल ने वैधीकरण अधिनियम को लागू करते हुए अपने विवेक से यह निर्णय लिया है कि अनुपात या आनुपातिक आधार पर लाभों का अनुदान सार्वजनिक हित में है और प्रोत्साहन पैकेज योजना के उद्देश्य को पूरा करता है। वैधीकरण अधिनियम न केवल धारा 93 के आशय और उद्देश्य को पूरा करता है, जैसा कि मूल रूप से तैयार किया गया था, बल्कि सार्वजनिक हित के साथ-साथ राज्य को लाभान्वित करने के साधन के रूप में प्रोत्साहन पैकेज योजना के अंतर्निहित उद्देश्यों को भी पूरा करता है और राज्य पर भारी वित्तीय नुकसान लादकर इन उद्देश्यों को रद्द करने से बचाता है। राज्य के वकील का एक अन्य निवेदन यह था कि पूर्वव्यापी

अधिनियम को इस आधार पर लागू नहीं किया जा सकता है कि पूर्वव्यापी लेवी ने डीलरों को उपभोक्ताओं को कर देने का कोई अवसर नहीं दिया, जैसा कि हीरालाल रतनलाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1973) 1 एस. सी. सी. 216 में कहा गया है।

19. दोनों पक्षों की उपरोक्त दलीलों पर विचार करने से पहले, उच्च न्यायालय के विवादित फैसले का अध्ययन करना उचित होगा ताकि उन कारणों का पता लगाया जा सके जो अपीलार्थियों की दलीलों को खारिज करने में उच्च न्यायालय के पक्ष में हैं।

20. उच्च न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से पता चलेगा कि 1988,1993 की योजना के सार और अधिनियम की धारा 41बीबी के रूप में वैधानिक प्रावधानों और समय-समय पर उसमें संशोधन (जो हम पहले ही ऊपर बता चुके हैं) और दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें दर्ज करने के बाद, उच्च न्यायालय ने मुख्य मुद्दे पर विचार किया, अर्थात 'विधान और पूर्वव्यापीता को मान्य करना'। यह इंगित करने के बाद कि किसी विषय पर कानून बनाने की शक्ति जो विधायिका की क्षमता के भीतर आती है, उसके दायरे में आती है, संभावित और साथ ही पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ कानूनों का अधिनियमन, उच्च न्यायालय ने एक और कानूनी सिद्धांत भी स्पष्ट किया, अर्थात्, जहां कोई कानून एक दुर्बलता से ग्रस्त है जो उच्च न्यायालय के फैसले में नोट किया गया है, विधायिका के लिए उस दोष को ठीक करने की अनुमति है जो न्यायालय द्वारा पाया गया है। इसे मान्य करने वाली प्रकृति के विधान के रूप में जाना जाता है, जो संवैधानिक रूप से अनुज्ञेय है क्योंकि इस तरह का मान्य करने वाला कानून पहले के विधान में दोष या बुराई को दूर करने की प्रकृति का है। इसके बाद उच्च न्यायालय ने उपरोक्त दोहरे सिद्धांतों पर विभिन्न निर्णयों का उल्लेख किया और उद्धृत किया, अर्थात्, एक कानून को संभावित रूप से और साथ ही पूर्वव्यापी रूप से अधिनियमित करने और एक मान्यकारी अधिनियम पारित करने की विधायिका की शक्ति। इसके बाद, उच्च

न्यायालय अपीलार्थियों के इस तर्क पर चर्चा करने के लिए आगे बढ़ा कि 2009 का संशोधन अधिनियम, सारतः, एक नए शुल्क को लागू करने के बराबर है और पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ एक नए शुल्क को लागू करना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन था और इस तर्क को यह पता लगाने के बाद खारिज कर दिया कि विधायी इरादे को केवल बिक्री या खरीद के कारोबार के उस हिस्से पर लाभ दिया गया था जो सरकार द्वारा निर्धारित अनुपात को लागू करके प्राप्त किया जा सकता है। सरकार ने इस अनुपात को निर्धारित किया लेकिन नियमों के रूप में वैधानिक अधिसूचना जारी करने के बजाय प्रशासनिक परिपत्र जारी करके गलत तरीका चुना। यह वही है जो मान्यकारी अधिनियम द्वारा प्राप्त किया जाता है और इसलिए यह कोई नया शुल्क नहीं था।

21. उच्च न्यायालय ने इस बात पर भी चर्चा की है कि उपरोक्त प्रकार का विधान विधान को मान्य करने की प्रकृति का होगा क्योंकि पहले के निर्णय के आधार को ही पूर्ववत करने की मांग की गई थी।

22. इसके साथ हम अपीलार्थियों द्वारा दिए गए तर्कों का विज्ञापन करते हैं। हम उन तर्कों पर पहले ही ध्यान दे चुके हैं। यह इंगित करना उचित है कि बहस के समय, अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने इस कानूनी प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था कि विधायिका पूर्वव्यापी रूप से कानूनों को लागू करने में सक्षम है। हालाँकि, श्री अनिल श्रीवास्तव ने हमारे सामने तर्क दिया है कि पूर्वव्यापी संशोधन अस्पष्टता को दूर करने या अयोग्यता के कारण को ठीक करने का प्रयास नहीं करता है, बल्कि संक्षेप में, यह कर का एक नया शुल्क लगाने का प्रयास करता है। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि पूर्वव्यापी प्रभाव से किए गए संशोधन का एकमात्र उद्देश्य बॉम्बे उच्च न्यायालय के पहले के फैसले के प्रभाव को बेअसर करना था। हम उपरोक्त दलीलों को स्वीकार करने में असमर्थ हैं और पाते हैं कि उच्च न्यायालय मामले के इस पहलू को सही परिप्रेक्ष्य

में देखने के लिए आगे बढ़ा है। उपरोक्त तर्क को खारिज करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि बॉम्बे बिक्री कर अधिनियम की धारा 41बीबी को वर्ष 2001 में इस क़ानून में शामिल किया गया था। इस प्रावधान की शुरुआत एक गैर-अस्थाई प्रावधान द्वारा की गई थी जो प्रोत्साहनों की किसी भी पैकेज योजना में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद संचालित होना था। इस धारा में विशेष रूप से प्रावधान किया गया है कि पात्र इकाई केवल बिक्री या खरीद के अपने कारोबार के उस हिस्से पर लाभ प्राप्त करने की हकदार होगी जो उस वर्ष इकाई की बिक्री या खरीद के कुल कारोबार के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुपात को लागू करके प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 41 बी. बी. एक सक्षम प्रावधान नहीं था, लेकिन इसमें प्रतिबंधों के रूप में एक विधायी आदेश था कि प्रोत्साहनों की किसी भी पैकेज योजना में कुछ भी निहित होने के बावजूद, पात्रता प्रमाण पत्र रखने वाली एक योग्य इकाई केवल बिक्री और खरीद के अपने कारोबार के उस हिस्से पर लाभ प्राप्त करने की पात्र होगी जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुपात को लागू करके प्राप्त किया जाएगा। इसलिए, उपरोक्त प्रावधान के पीछे विधायी इरादा स्पष्ट रूप से प्रकट था अर्थात केवल आनुपातिक आधार पर लाभ की अनुमति देना। हालांकि, साथ ही, यह अनुपात निर्धारित करने के लिए सरकार पर छोड़ दिया गया था जिसके आधार पर बिक्री और खरीद के कारोबार का केवल एक हिस्सा प्रोत्साहन के लिए योग्य होगा। इसी तरह, जब एम. वी. ए. टी. अधिनियम लागू किया गया था, तो बिक्री कर अधिनियम की धारा 41 बी. बी. में निहित समान प्रावधान को एम. वी. ए. टी. अधिनियम की धारा 93 (1) के रूप में शामिल किया गया था। यह इस वैधानिक प्रावधान का कार्यान्वयन है जिसमें सरकार ने गलती की है। हालाँकि, सरकार ने 17 जनवरी, 1998 को परिपत्र जारी करके उस इरादे को पूरा किया, जिसमें अनुपात निर्धारित करके केवल योग्य इकाई की बिक्री या खरीद के कारोबार के उस हिस्से पर लाभ प्रदान किया गया था, लेकिन ऐसा करने का तरीका

दोषपूर्ण था। इसे नियमों के माध्यम से निर्धारित करने के बजाय, जो कि उचित प्रक्रिया थी, 1993 की योजना के तहत प्रोत्साहनों के उपयोग पर एक सीमा लागू करने में एक प्रशासनिक परिपत्र के माध्यम से उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास किया गया था। इस कानूनी कमी के कारण इस परिपत्र को उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था। उच्च न्यायालय के अनुसार, यह वह दोष है जिसे पूर्वव्यापी रूप से उक्त संशोधन करके वैधानिक प्रावधान में संशोधन करके ठीक करने की कोशिश की गई थी। उपरोक्त आधार पर, उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाकर्ताओं के इस तर्क को खारिज कर दिया कि पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ एक नया शुल्क लगाया गया था।

23. इस बात पर जोर देना प्रासंगिक होगा कि 2001 के संशोधन अधिनियम 22 के माध्यम से संशोधन द्वारा धारा 41 बीबी को शामिल करने के समय, विधेयक को पेश करने के साथ उद्देश्यों और कारणों के विवरण में विशेष रूप से कहा गया था कि संशोधन का उद्देश्य 'राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों में स्थित विस्तार इकाइयों में निर्मित वस्तुओं के अनुपात में प्रोत्साहन अनुदान को प्रतिबंधित करना' था। इस प्रकार, योग्य इकाइयों को आनुपातिक आधार पर प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए उक्त प्रावधान को शामिल करके विधायी इरादे को प्रकट किया गया था। एम. वी. ए. टी. अधिनियम के प्रावधानों से इसी तरह के इरादे को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। हम पहले ही उक्त अधिनियम की धारा 93 (1) को पुनः प्रस्तुत कर चुके हैं जो विशेष रूप से 'कुछ आकस्मिकताओं में एक योग्य इकाई को आनुपातिक प्रोत्साहन' प्रदान करती है।

24. प्रोत्साहन पैकेज योजना के संबंध में प्रासंगिक प्रावधानों पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण होगा। एम. वी. ए. टी. अधिनियम के अध्याय XIV में प्रोत्साहन पैकेज योजना के संबंध में प्रावधान हैं। धारा 88 (ए) "पात्रता प्रमाण पत्र" शब्द को प्रोत्साहनों की प्रासंगिक पैकेज योजना के तहत बिक्री कर प्रोत्साहन के संबंध में आयुक्त द्वारा जारी

प्रमाण पत्र के रूप में परिभाषित करती है। "पात्रता प्रमाणपत्र" शब्द को धारा 88 (सी) में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई प्रोत्साहनों की पैकेज योजना के तहत बिक्री कर प्रोत्साहन के संबंध में एस. आई. सी. ओ. एम. या उद्योग निदेशक द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र है। धारा 88 के खंड (बी) के तहत एक योग्य इकाई का अर्थ एक औद्योगिक इकाई है जिसके संबंध में एक पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। धारा 88 के खंड (ई) के तहत "प्रोत्साहन की पैकेज योजना" अभिव्यक्ति में 1988 और 1993 की योजनाएं शामिल हैं। धारा 89 (1) में कहा गया है कि जहां राज्य सरकार द्वारा घोषित प्रोत्साहनों की किसी भी पैकेज योजना के तहत कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा किसी योग्य इकाई को पात्रता प्रमाण पत्र की सिफारिश की गई है, ऐसी पात्र इकाई आयुक्त को पात्रता प्रमाण पत्र देने के लिए आवेदन कर सकती है। आयुक्त को यह संतुष्ट होने पर कि इकाई निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करती है, धारा 89 की उप-धारा (2) के तहत पात्रता का प्रमाण पत्र देने का अधिकार है। धारा 90 (ए) में कहा गया है कि पात्रता प्रमाण पत्र उस तारीख को रद्द कर दिया जाएगा जिस तारीख को: (i) योग्य इकाई के लिए निर्धारित मौद्रिक सीमा से अधिक लाभों की संचयी मात्रा सहित प्रोत्साहन; या (ii) वह अवधि जिसके लिए किसी योग्य इकाई को पात्रता प्रमाण पत्र दिया गया था, समाप्त हो जाता है; या (iii) किसी योग्य इकाई को दिया गया पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द कर दिया गया है। धारा 91 की उप-धारा (1) में कहा गया है कि जहां प्रोत्साहन के पैकेज योजनाओं के तहत किसी इकाई को हकदारी का प्रमाण पत्र दिया गया है और ऐसी इकाई किसी भी अवधि के लिए लाभ प्राप्त करने की हकदार है जो नियत दिन के बाद समाप्त होने वाली है, तो योजना में कुछ भी निहित होने के बावजूद, लाभ केवल अधिनियम, नियमों और उसके तहत जारी अधिसूचनाओं के अनुसार ही प्राप्त किए जाएंगे।

25. यह उपरोक्त पृष्ठभूमि/चीजों की योजना में धारा 93 (1) आनुपातिक प्रोत्साहन प्रदान करती है। एक बार जब हम पाते हैं कि शुरुआत से ही वैधानिक योजना ने आनुपातिक प्रोत्साहन प्रदान किया था और इस विधायी इरादे को उद्देश्यों और कारणों में भी व्यक्त किया गया था, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि 2009 से पहले इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था और इस तरह का प्रावधान पहली बार वर्ष 2009 में जोड़ा गया था।

26. अपीलार्थियों के इस तर्क पर आते हुए कि 2009 के संशोधन का प्रभाव न्यायालय के निर्णय को निष्प्रभावी या निरस्त करने के लिए था, हम इसे ऐसा नहीं पाते हैं। उच्च न्यायालय ने पी वी टेक्सटाइल्स मामले में बिक्री कर न्यायाधिकरण के पहले के फैसले का सही विश्लेषण किया है, जिसके बाद उच्च न्यायालय की खंड पीठ के साथ-साथ मायर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मामले में अपने पहले के फैसले का भी विश्लेषण किया है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि पी वी टेक्सटाइल्स मामले में उच्च न्यायालय ने वस्तुओं और कारणों के विवरण को देखने के बाद, बिक्री कर अधिनियम में धारा 41 बी. बी. के उद्देश्य को निम्नलिखित शब्दों में समझाते हुए इस तथ्य को मान्यता दीः "30". यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उक्त धारा राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में स्थित विस्तार इकाई में निर्मित वस्तुओं के अनुपात में प्रोत्साहन अनुदान को प्रतिबंधित करने की दृष्टि से पेश की गई है।

27. इस प्रकार, पी वी टेक्सटाइल्स के मामले में निर्णय देते समय, उच्च न्यायालय ने स्वीकार किया कि बिक्री कर अधिनियम की धारा 41 बीबी के पीछे का उद्देश्य विस्तार इकाई में निर्मित वस्तुओं के अनुपात में प्रोत्साहन अनुदान को प्रतिबंधित करना था। इसके बावजूद, परिपत्र को रद्द करने का एकमात्र कारण यह था कि उपरोक्त प्रावधान का प्रभाव एक प्रशासनिक आदेश के रूप में दिया गया था, जबकि

कानून के लिए आवश्यक है कि उचित तरीका नियम बनाकर इसे प्रभावी बनाना था। यह निर्णय का आधार है और यह वह आधार है जो विधायी संशोधन द्वारा पूर्वव्यापी रूप से छीन लिया गया है। इन परिस्थितियों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि इरादा न्यायालय के फैसले को रद्द करने का था। स्पष्ट इरादा अधीनस्थ विधान यानी वैधानिक नियमों के रूप में विधायी इरादे को लागू नहीं करने में कार्यपालिका द्वारा की गई पिछली त्रुटि को सुधारना और प्रशासनिक कार्रवाई द्वारा इसे प्राप्त करने का प्रयास करना था।

28. दोनों पक्षों के वकीलों ने कानून को मान्य करने के विषय पर कई फैसलों का हवाला दिया है। वास्तव में, इनमें से अधिकांश निर्णय सामान्य हैं, जिन्हें दोनों पक्षों द्वारा संदर्भित किया जाता है। उन निर्णयों के अनुपात को उनके अपने तरीके से पढ़ने का प्रयास किया गया था। हालांकि, एक बार जब तथ्यात्मक आधार स्पष्ट हो जाता है, तो इन निर्णयों में कहा गया कानून स्पष्ट रूप से प्रतिवादी के पक्ष में झुकता है। इन सभी निर्णयों का उल्लेख करने के बजाय, हमारे उद्देश्य को ऐसे कुछ निर्णयों पर ध्यान देकर पूरा किया जाएगा जो सीधे लागू होते हैं।

29. राय रामकृष्ण बनाम बिहार राज्य, ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1667 में, जो संविधान पीठ का एक निर्णय है, इस सिद्धांत को निम्नलिखित तरीके से समझाया गया थाः

> "दूसरा बिंदु जिस पर हमारे सामने कोई विवाद नहीं है, वह यह है कि तीन सूचियों में कई प्रविष्टियों द्वारा कवर किए गए विषयों के संबंध में कानून बनाने के लिए उपयुक्त विधानसभाओं को प्रदत्त विधायी शक्ति का उपयोग संभावित और पूर्वव्यापी दोनों तरह से किया जा सकता है। जहां विधायिका एक वैध कानून बना सकती है, वह न

केवल उक्त कानून के भौतिक प्रावधानों के संभावित संचालन के लिए प्रावधान कर सकती है, बल्कि यह उक्त प्रावधानों के पूर्वव्यापी संचालन के लिए भी प्रावधान कर सकती है। इसी तरह, इसमें कोई संदेह नहीं है कि विचाराधीन विधायी शक्ति में उन कानूनों को मान्य करने के लिए सहायक या सहायक शक्ति शामिल है जो अमान्य पाए गए हैं। यदि किसी विधायिका द्वारा पारित किसी कानून को अदालतों द्वारा किसी एक या किसी अन्य कमी के लिए अमान्य होने के रूप में निरस्त कर दिया जाता है, तो यह उपयुक्त विधायिका के लिए उक्त कमी को ठीक करने और एक मान्य कानून पारित करने के लिए सक्षम होगा ताकि उक्त पूर्व कानून के प्रावधानों को पारित होने की तारीख से प्रभावी बनाया जा सके। यह स्थिति संयुक्त प्रांत बनाम अतीका बेगम के मामले में संघीय न्यायालय के फैसले के बाद से दृढ़ता से स्थापित की गई है।" (जोर दिया गया)

30. हम एपरी चिन्ना कृष्ण मूर्ति बनाम उड़ीसा राज्य, ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 1581 के मामले में एक अन्य संविधान पीठ के फैसले के निम्नलिखित अंश को भी उद्धृत करना चाहेंगेः

"10...तर्क यह है कि छूट देने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदान की गई है और इसका उपयोग राज्य सरकार द्वारा वैध रूप से किया गया था और हालांकि विधायिका ऐसी छूट को वापस ले सकती है, लेकिन वह ऐसा पूर्वव्यापी रूप से नहीं कर सकती है। यह स्पष्ट है कि यदि राज्य सरकार जो विधायिका की प्रतिनिधि है, उसके द्वारा दी गई छूट को वापस ले सकती है, तो विधायिका को इस अधिकार से वंचित

नहीं किया जा सकता है। लेकिन यह आग्रह किया जाता है कि एक बार छूट वैध रूप से दी जाने के बाद, विधायिका इसे पूर्वव्यापी रूप से वापस नहीं ले सकती है, क्योंकि यह अधिसूचना को ही अमान्य कर देगा। हम इस तर्क से प्रभावित नहीं हैं। विधानमंडल ने विवादित अधिनियम की धारा 2 द्वारा जो करने का इरादा किया है, वह अधिसूचना के इरादे को स्पष्ट करना है। धारा 2 सार में घोषणा करती है कि छूट देने वाली अधिसूचना जारी करने में प्रतिनिधि का इरादा उक्त छूट का लाभ केवल उन व्यक्तियों तक सीमित रखना था जो वास्तव में सोने के आभूषणों का उत्पादन करते हैं या उस उद्देश्य के लिए कारीगरों को नियुक्त करते हैं। हम यह नहीं देखते हैं कि वर्तमान चर्चा में विधायी अक्षमता का कोई सवाल कैसे आ सकता है। और, यदि राज्य सरकार को छूट देने या वापस लेने की शक्ति दी गई थी, तो यह संभवतः उस संबंध में कोई भी प्रावधान करने की विधायिका की क्षमता को संभावित या पूर्वव्यापी रूप से प्रभावित नहीं कर सकता है। इसलिए, इस तर्क में कोई सार नहीं है कि विवादित अधिनियम की धारा 2 का पूर्वव्यापी संचालन अमान्य है।

वर्तमान मामले में भी, जैसा कि पहले देखा गया है, विधायिका ने राज्य सरकार को वह अनुपात/अनुपात निर्धारित करने की शक्ति दी थी जिसमें लाभ दिया जाना था। राज्य सरकार ने उस पर कार्रवाई की, लेकिन गलत तरीके से सत्ता का प्रयोग किया। वैधानिक प्रावधान के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, राज्य विधानमंडल ने स्वयं पूर्वव्यापी रूप से धारा में संशोधन करके स्थिति को सुधार लिया। इस प्रकार,

उपरोक्त निर्णय का अनुपात वर्तमान मामले की तथ्य स्थिति पर पूरी तरह से लागू होता है।"

31. इस न्यायालय ने हीरालाल रतनलाल में कानून को मान्य करने के कानून को फिर से समझाया था। उस मामले में, उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम, 1948 की धारा 3-डी अनाज और दालों सहित खाद्यान्नों के मामले में एक व्यापारी द्वारा की गई पहली खरीद के कारोबार पर एकल बिंदु कर लगाती है। एक अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें एक निश्चित दर पर खाद्यान्न की पहली खरीद पर शुल्क लगाने का प्रावधान किया गया था। उस मामले में अपीलार्थी विभाजित या प्रसंस्कृत खाद्यान्न और दाल का विक्रेता था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक निर्णय के बाद विधायिका ने वैध कानून बनाया। इस मान्यकारी विधान को निम्नलिखित तरीके से विधायिका का एक वैध अभ्यास माना गया थाः

" ... इस अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि विधानमंडल मूल अधिनियम में असंकलित या असंकलित दालों से संसाधित या विभाजित दालों को अलग करने के अपने इरादे को स्पष्ट रूप से सामने लाने में विफल रहा। इसके अलावा पूर्वव्यापी संशोधन आवश्यक हो गया क्योंकि अन्यथा राज्य को बड़ी राशि वापस करनी होगी। यह तर्क कि पूर्वव्यापी लेवी ने विक्रेताओं को उपभोक्ताओं को देय कर को पारित करने का कोई अवसर नहीं दिया, इसकी अधिक वैधता नहीं है। विक्रेता पर कर लगाया जाता है; यह तथ्य कि उसे कर को उपभोक्ताओं को देने की अनुमति है या वह आम तौर पर उपभोक्ता को देने की स्थिति में है, जब हम विधायी क्षमता पर विचार करते हैं तो इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है।"

32. हम बख्तावर ट्रस्ट बनाम एम. डी. नारायण, (2003) 5 एस. सी. सी. 298 में इस न्यायालय के फैसले से निम्नलिखित चर्चा को भी पुनः प्रस्तुत करना चाहेंगेः

"25. विधायिका के लिए यह खुला है कि वह पूर्वव्यापी रूप से कानून में बदलाव करे, बशर्ते कि बदलाव इस तरह से किया जाए कि अदालत के लिए उसी फैसले पर पहुंचना संभव नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, पहले के फैसले के आधार को उखाड़ फेंका जाना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप उन परिस्थितियों में मौलिक परिवर्तन होता है जिन पर यह स्थापित किया गया था।

26. जहाँ कोई विधायिका किसी न्यायालय द्वारा घोषित वैधानिक प्रावधानों के प्रतिकूल कार्यकारी कार्रवाई को मान्य करती है, वहाँ विधायिका को पहले अयोग्यता के आधार को हटाना और फिर कार्यकारी कार्रवाई को मान्य करना आवश्यक है। किसी कार्यकारी कार्रवाई या किसी कानून के किसी प्रावधान को मान्य करने के लिए, विधायिका के लिए यह घोषणा करना पर्याप्त नहीं है कि अदालत द्वारा दी गई न्यायिक घोषणा बाध्यकारी नहीं होगी, क्योंकि विधायिका के पास वह शक्ति नहीं है। कानून की अदालत के निर्णय का एक बाध्यकारी प्रभाव होता है जब तक कि जिस आधार पर इसे दिया गया है, उसमें इतना बदलाव नहीं किया जाता है कि उक्त निर्णय बदली हुई परिस्थितियों में नहीं दिया जाता।"

33. भारतीय एल्यूमीनियम कंपनी बनाम केरल राज्य (1996) 7 एस. सी. सी. 637 के मामले में निर्णय का उल्लेख करना भी उपयोगी हो सकता है, जिसमें

न्यायालय ने इस मुद्दे पर पहले के निर्णयों पर ध्यान देते हुए इस पहलू पर निर्धारित सिद्धांतों को समाप्त कर दिया था। हम उसी को पुनः प्रस्तुत करना चाहेंगेः

"56. उपरोक्त निर्णयों के सारांश से निम्नलिखित सिद्धांत सामने आएंगेः

(1) पक्षों के अधिकारों का निर्णय आवश्यक न्यायिक कार्य है। विधायिका को आचरण या नियमों के मानदंड निर्धारित करने होते हैं जो पक्षों और लेन-देन को नियंत्रित करेंगे और अदालत से उन्हें प्रभावी बनाने की आवश्यकता होती है;

(2) संविधान ने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका द्वारा संप्रभु शक्ति के प्रयोग में नाजुक संतुलन को चित्रित किया है;

(3) कानून के शासन द्वारा शासित लोकतंत्र में, विधायिका अनुच्छेद 245 और 246 के तहत शक्ति का प्रयोग करती है और सातवीं अनुसूची में संबंधित सूचियों में प्रविष्टियों के साथ पढ़े गए अन्य सहयोगी लेख कानून बनाने के लिए करते हैं जो कानून में संशोधन करने की शक्ति को छुपाता है।

(4) न्यायालयों को अपनी चिंता और न्यायिक शक्ति को समान रूप से संरक्षित करने के प्रयास में तीन संप्रभु अधिकारियों के बीच संविधान द्वारा तैयार किए गए नाजुक संतुलन को बनाए रखने के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए। कानून का शासन एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने के संवैधानिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, संबंधित संप्रभु कार्यकर्ताओं को अपने जोड़ों में स्वतंत्र

रूप से खेलने की आवश्यकता होती है ताकि सामाजिक प्रगति और व्यवस्था की प्रगति निर्बाध रहे। नाजुकता के साथ निर्मित सुचारू संतुलन को हमेशा बनाए रखा जाना चाहिए।

(5) न्यायिक शक्ति की रक्षा के लिए इसकी चिंता में, अत्यधिक उत्साही होना और न्यायिक संरक्षण में घुसपैठ करना अनावश्यक है जो सक्षम रूप से बनाए गए वैध कानून को अमान्य करता है।

(6) इसलिए, न्यायालय को यह पता लगाने के लिए कानून की सावधानीपूर्वक जांच करने की आवश्यकता है; (क) क्या अदालत द्वारा बताए गए दोष और पिछली कानून द्वारा पीड़ित अयोग्यता को कानूनी और संवैधानिक आवश्यकताओं का पालन करते हुए ठीक किया जाता है; (ख) क्या विधायिका को कानून को मान्य करने की क्षमता है; (ग) क्या ऐसा सत्यापन संविधान के भाग III में गारंटीकृत अधिकारों के अनुरूप है।

(7) न्यायालय के पास किसी अमान्य कानून को मान्य करने या अवैध रूप से बनाए गए और एकत्र किए गए कर के ढोंग को वैध बनाने या अमान्य होने के मानदंड को हटाने या कोई उपाय प्रदान करने की शक्ति नहीं है। ये न्यायिक कार्य नहीं हैं बल्कि विधायिका के अनन्य प्रांत हैं। इसलिए, वे न्यायिक शक्ति का अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं।

(8) विधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए, विधायिका केवल घोषणा करके, बिना किसी और चीज़ के, किसी न्यायिक निर्णय को सीधे रद्द, संशोधित या ओवरराइड नहीं कर सकती है। यह न्यायिक निर्णय को

अपने विधायी क्षेत्र के भीतर इस विषय पर वैध कानून बनाकर मूल रूप से इसके चरित्र को पूर्वव्यापी रूप से बदल या बदलकर अप्रभावी बना सकता है। परिवर्तित या परिवर्तित शर्तें ऐसी होती हैं कि न्यायालय द्वारा पिछला निर्णय नहीं दिया जाता, यदि वे शर्तें कानून को अमान्य घोषित करने के समय मौजूद होतीं। इसे पूर्वव्यापी कानून को एक डीमिंग तिथि के साथ या एक विशेष तिथि से प्रभावी बनाने का भी अधिकार है। विधायिका कर या शुल्क के स्वरूप को अनुज्ञेय से अनुमेय कर में बदल सकती है, लेकिन कर या लेवी को इस तरह के चरित्र का जवाब देना चाहिए और विधायिका विषय से वसूली के लिए अमान्य आधार को हटाने या राज्य से वसूली को अप्रभावी बनाने पर ऐसे कर को मान्य करने वाले अमान्य कर की वसूली करने में सक्षम है। विधायिका के लिए यह सक्षम है कि वह पूर्वव्यापी प्रभाव से कानून बनाए और अपनी एजेंसियों को उस आधार पर कर लगाने और एकत्र करने के लिए अधिकृत करे, न्यायालय द्वारा घोषणा या उसकी वसूली के लिए दिए गए निर्देश के बावजूद, एकत्र किए गए कर के अधिरोपण और कर की वसूली को वैध बनाए।

(9) इस न्यायालय के सभी निर्णयों में जो सुसंगत सूत्र चलता है, वह यह है कि विधायिका सीधे निर्णय को रद्द नहीं कर सकती है या कोई निर्देश नहीं दे सकती है जो उस पर बाध्यकारी नहीं है, लेकिन उसके पास उस आधार को हटाकर निर्णय को अप्रभावी बनाने की शक्ति है, जिसके आधार पर निर्णय दिया गया था, जो संविधान के कानून के अनुरूप है और विधायिका को ऐसा करने की क्षमता होनी चाहिए।

34. उपरोक्त निर्णय का पालन इस न्यायालय ने सहायक कृषि आयकर आयुक्त और अन्य बनाम नेटली 'बी' एस्टेट और अन्य, (2015) 11 एस. सी. सी. 462 में किया है। आर. सी. टोबैको (पी) लिमिटेड बनाम भारत संघ, (2005) 7 एस. सी. सी. 725 में इस न्यायालय का निर्णय इसी प्रभाव का है।

35. श्री गणेश की दलीलों को ध्यान में रखते हुए, शुरुआत में यह उल्लेख किया जा सकता है कि उच्च न्यायालय में ऐसी कोई दलील नहीं दी गई थी। श्री गणेश के तर्क का जोर यह था कि इस संशोधन ने औद्योगिक इकाइयों को अविश्वास में डाल दिया है और उन्हें अपने उत्पादन के किसी भी हिस्से पर वैट की वसूली से रोक दिया है। इस तरह के तर्क के लिए एक तथ्यात्मक आधार होना चाहिए। किसी भी मामले में, हम तर्क में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। प्रत्यर्थी के विद्वान वकील द्वारा यह विशेष रूप से बताया गया था कि इन सभी अपीलार्थियों ने आनुपातिक लाभ प्राप्त किया है जो वैधानिक प्रावधान के तहत अनुमेय था। अब इरादा उनके संबंधित विस्तारित उपक्रम के पूरे कारोबार पर लाभ का दावा करना है, जो किसी भी मामले में अनुमेय नहीं था। इसके अलावा, उपभोक्ता पर बोझ डालने में सक्षम नहीं होने का ऐसा तर्क असमर्थनीय है। बहुत पहले वर्ष 1961 में, जे. के. जूट मिल्स कं. लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 1534 मामले में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने निम्नलिखित सिद्धांत निर्धारित किया थाः

> "(i) जहां वस्तुओं की बिक्री होती है, राज्य विधानमंडल कर लगाने में सक्षम है और संवैधानिक सीमाओं के अधीन, ऐसा कर उन बिक्री पर भी लगाया जा सकता है जो अधिनियम से पहले हुई हैंः
>
> " लेकिन जहां लेनदेन माल की बिक्री का है जैसा कि कानून को पता है, उस पर कर लगाने की राज्य की शक्ति पूर्ण और अप्रतिबंधित

है, केवल किसी भी सीमा के अधीन है जो संविधान लागू कर सकता है, और उस शक्ति का प्रयोग करते हुए, यह विधानमंडल पर कर लगाने के लिए सक्षम होगा।"

(ii) हालांकि आम तौर पर एक बिक्री कर खरीदार को देने का इरादा है, लेकिन विधायिका की शक्ति बोझ को पारित करने पर सशर्त नहीं हैः

"इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक बिक्री कर, स्वीकृत धारणाओं के अनुसार, खरीदार को पारित करने का इरादा है, और विक्रेता द्वारा खरीददार से बिक्री कर के संग्रह को अधिकृत और विनियमित करने वाले प्रावधान बिक्री कर कानून की एक सामान्य विशेषता है। लेकिन यह बिक्री कर की एक अनिवार्य विशेषता नहीं है कि विक्रेता को इसे उपभोक्ता को देने का अधिकार होना चाहिए, और न ही विक्रेताओं के लिए खरीददारों से कर एकत्र करने का प्रावधान करने पर बिक्री पर कर लगाने की विधायिका की शक्ति सशर्त है। क्या कोई कानून बनाया जाना चाहिए, बिक्री कर लगाया जाना चाहिए, या बिक्री कर के अधिरोपण को मान्य करना चाहिए, जब विक्रेता इसे उपभोक्ता पर डालने की स्थिति में नहीं है, यह नीति का विषय है और यह विधायिका की क्षमता को प्रभावित नहीं करता है। यह प्रश्न टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य, (1958) एस. सी. आर. 1355: (ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 452) मामले में इस अदालत के फैसले से समाप्त होता है।

(iii) विधायिका के पास एक पूर्ण शक्ति है, जो एक कानून को अधिनियमित करने के लिए संवैधानिक सीमाओं के अधीन है जो संभावित या पूर्वव्यापी हैः "एक विधायिका की शक्ति उसे सौंपे गए विषय के संदर्भ में एक कानून बनाने के लिए, जैसा कि पहले ही कहा गया है, केवल संविधान द्वारा लगाई गई किसी सीमा के अधीन है। इस तरह की शक्ति के प्रयोग में, विधायिका एक कानून बनाने में सक्षम होगी, जो या तो संभावित या पूर्वव्यापी हो।

36. यह इंगित करना भी उचित होगा कि आर. सी. में टोबैको (पी) लिमिटेड मामले में, इस न्यायालय ने आधिकारिक रूप से इस तथ्य को घोषित किया कि जिस व्यापारी पर कर लगाया जाता है, वह उपभोक्ताओं पर कर लगाने की स्थिति में नहीं है, इसकी विधायिका की क्षमता के लिए कोई प्रासंगिकता नहीं है। इस संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियों पर ध्यान दिया जा सकता हैः

"48. याचिकाकर्ता जो समूह ए में थे, उन्होंने इसका खंडन किया है और तर्क दिया है कि बड़ी सिगरेट कंपनियों के साथ उनके संबंध मूलधन-से-प्रधान आधार पर थे और अपने समझौतों के तहत वे अकेले ही धारा 154 के तहत उत्तरदाताओं द्वारा अब मांगे गए उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

49. हम उठाए गए विवादों को निर्धारित करने की स्थिति में नहीं हैं। हालाँकि, हम इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि हालाँकि अन्य अप्रत्यक्ष करों की तरह उत्पाद शुल्क कानून के तहत माल के ग्राहक को दिया जा सकता है, जैसा कि अब है, यह उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं का निर्माता है जिसे उत्पाद शुल्क अधिकारी

भुगतान की तलाश करेंगे। निर्माता अपने ग्राहकों के साथ अपने दायित्व को कैसे समायोजित करेगा, यह उत्तरदाताओं से संबंधित नहीं है और न ही उन्हें उन व्यक्तियों से अपने बकाया की वसूली करने के लिए कहा जा सकता है जिन्होंने अंततः निर्माता के साथ एक समझौते के परिणामस्वरूप उत्पाद शुल्क का भुगतान करने की जिम्मेदारी ली हो। (इस संबंध में राजस्थान राज्य बनाम जे. के. उदयपुर उद्योग लिमिटेड [(2004) 7 एस. सी. सी. 673] एस. सी. सी. पी. 692) देखें।"

37. यह इंगित करना भी प्रासंगिक होगा कि आर. सी. टोबैको (पी) लिमिटेड में, इस न्यायालय ने पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ एक छूट अधिसूचना को रद्द करने को बरकरार रखा क्योंकि मूल रूप से बनाई गई अधिसूचना में पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान नहीं किए गए हैं जो प्रोत्साहन की नीति के अंतर्निहित उद्देश्य की उपलब्धि को सुनिश्चित करते। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि पूर्वव्यापी संशोधन द्वारा नीति के उद्देश्य की दोषपूर्ण अभिव्यक्ति को सुधारने की अनुमति है।

"26. छूट अधिसूचनाएँ केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 5-ए के तहत संसद के प्रतिनिधि के रूप में जारी की गई थीं। सरकार के मंत्रिमंडल रूप में, कार्यपालिका से विधायिका के विचारों को प्रतिबिंबित करने की उम्मीद की जाती है। विधायिकाओं के लिए विस्तार से निपटना और किसी क़ानून को लागू करने में उत्पन्न होने वाली असंख्य समस्याओं को पूरा करना असंभव होगा। जब कुछ मामलों में संसद द्वारा अधीनस्थ विधान की शक्ति प्रदान की जाती है तो यह केवल नीति और दिशानिर्देशों को निर्धारित कर सकती है और

उम्मीद कर सकती है कि कार्यपालिका द्वारा जो किया जाता है वह ऐसी नीति के अनुरूप है। यह निश्चित रूप से अपने प्रतिनिधि पर नियंत्रण बनाए रखता है और प्रतिनिधि की कार्रवाई को निरस्त करके उस नियंत्रण का प्रयोग कर सकता है। [सीता राम बिशंभर दयाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1972) 4 एस. सी. सी. 485:1974 एस. सी. सी. (कर) 294: (1972) 2 एस. सी. आर. 141; एम. के. पापिया एंड संस बनाम उत्पाद शुल्क आयोग, (1975) 1 एस. सी. सी. 492:1975 एस. सी. सी. (कर) [28] नतीजतन, यदि कार्यपालिका संसद के उद्देश्य को पूरा करने में विफल रही है, तो इस तरह के नियंत्रण का प्रयोग कार्यपालिका को जो हासिल करना चाहिए था उसे पूर्वव्यापी रूप से अधिनियमित करके किया जा सकता है।"

38. उपरोक्त तथ्यात्मक और कानूनी चर्चा के दृष्टिकोण में, श्री गणेश द्वारा पश्चिम बंगाल होजरी एसोसिएशन और अन्य में इस न्यायालय के निर्णयों पर निर्भरता पूरी तरह से असमर्थनीय है क्योंकि वे इस मामले के संदर्भ में लागू नहीं होते हैं।

39. इस प्रकार, हम इनमें से किसी भी अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं क्योंकि हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने विवादित संशोधन की वैधता को बरकरार रखते हुए इस मुद्दे पर उचित रूप से विचार किया है। नतीजतन, ये अपील विफल हो जाती हैं और लागत के साथ खारिज कर दी जाती हैं।

कल्पना के. त्रिपाठी — अपील खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता अनुवादक सपना राजपुरोहित द्वारा किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा मे समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।